

भारत डोगरा
 (बाड़मेर, राजस्थान)

बाड़मेर में दूर-दूर तक फैले रेत के टीलों और उसमें यदा-कदा बिखरी बस्तियों या ढाणियों में एक सवाल सबके सामने उभर कर खड़ा हो चुका है – चारे और पानी का संकट जब मार्च-अप्रैल में ही उपस्थित हो चुका है तो आने वाले गर्मी के महीनों में क्या हाल होगा?

राजस्थान में थार रेगिस्तान के जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे विकट स्थिति है बाड़मेर की। यहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना का थोड़ा सा जल भी नहीं पहुंचा है। एक तो वर्षा वैसे ही देश के औसत से भी बहुत कम होती है पर पिछले वर्ष तो यहां वर्षा जैसे झांकने भर को आई। मात्र 52 किलोमीटर की वर्षा दर्ज की गई। एकफसली इस इलाके की खरीफ की फसल पहले से तबाह हो रहे किसानों को और कर्जग्रस्त करती हुई लगभग पूरी तरह नष्ट ही गई। सभी 1975 गांव पूरी तरह सूखे से प्रभावित घोषित हो चुके हैं।

भारत पाक सीमा के पास स्थित भीलों के तला गांव की ओर जाते हुए यह लेखक एक छोटे कुएं के पास रुका। यहां एक छोटे से पर बहुत गहरे कुएं से तीन व्यक्ति आपसी सहयोग से लगभग दो सौ फीट लंबी रस्सी की मदद लेकर पानी निकाल रहे थे। पानी इतना गहरा था कि नजर नहीं आता था। उसमें चमड़े का थैला डालकर खींचते हुए दृ

व्यक्ति रस्सी का दूसरा कोना पकड़कर बहुत दूर तक चलते जाते थे। जब थैला ऊपर आता था तो तीसरा सदस्य (जो एक स्कूल का बच्चा था पर पानी लाने की जिम्मेदारी के कारण वह स्कूल छोड़, आया था) उसे कुएं के पास बनाए गए गड्ढे में डाल देता था।

इस तरह लगभग दस मटके पानी उस गड्ढे से निकालकर उसे कैनवास या मोटे कपड़े के उन थैलों में भरा गया जो एक ऊंट पर लदे थे। लगभग दो-तीन किलोमीटर दूर से वे पानी भरने आए थे उन्हें ऊंट सहित वहां वापस जाना था। इस तरह तीन व्यक्तियों व एक ऊंट ने लगभग पांच घंटे लगाकर दस मटके पानी का इंतजाम किया। वह भी इतना खारा पानी कि मुझसे तो पिया ही नहीं गया।

मेरे साथी सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम जी ने बताया — पानी की यह स्थिति तो अपेक्षाकृत बेहतर देख रहे हैं। गर्भियों में तो यहां पानी बहुत कम बचता है अतः पर्याप्त पानी उलब्ध हो इसके लिए इंतजार करने में कई घंटे कभी—कभी तो रात भर बैठना पड़ता है। कुछ समय बाद मैं धनऊ कस्बे की ओर जा रहा था तो सड़क किनारे पर ही मिला हड्डियों का एक विशाल ढेर थे उन मृत पशुओं की हड्डियां थीं जो इस सूखे संकट में चारे व पानी के अभाव में मर गए। जब मैं इनका चित्र लेने आगे बढ़ा तो गिर्द हड्डियों के आसपास तेजी से उड़ान भरने लगे। ये प्रतीक हैं पेयजल और चारे के उग्र होते संकट के। मई का महीना आते—आते सरकार को अधिकांश गांवों को पेयजल टैंकरों द्वारा उपलब्ध करवाना होगा। यह जल कहां से प्राप्त करना है इसका पूर्व नियोजन

रेगिस्तान का अकाल

संकट में है बाड़मेर

करना और उचित संख्या में टैंकरों की व्यवस्था करना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही पाईपलाईनों के अवैध कनेक्शन हटाने चाहिए ताकि जरूरतमंद बस्तियों तक पानी पहुंच सके। मुख्य बर्ती तक प्रायः टैंकर पानी पहुंच देते हैं पर प्रायः इनके आगे की ढाणियां चिंतित रह जाती हैं। ढाणियों तक पानी पहुंचाने में ऊंट सबसे उपयोगी है। ऊंट के माध्यम से पानी पहुंचाने में कई स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार भी

बढ़ने पर भी न्यूनतम चारे से पशु चिंतित हों, चारे की गुणवत्ता सुधारने की भी जरूरत है। कुछ व्यापारी बहुत ही घटिया, मिट्टी-रेत भरा चारा भेज रखे हैं। उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। गोवंश के अतिरिक्त भेड़, बकरी, ऊंट आदि अन्य महत्वपूर्ण पशुओं के लिए भी चारे-पानी की चिंता करनी चाहिए।

ऊंट को वैसे कहने को तो रेगिस्तान का जहाज कह दिया गया है पर उसकी

ऊंट को वैसे कहने को तो रेगिस्तान का जहाज कह दिया गया है पर उसकी रक्षा और संरक्षण की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि रेगिस्तान के लिए इतना उपयोगी पशु आज अपने घर में ही संकटग्रस्त हो चला है। खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर क्या आ गया कि ऊंट की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। पर पानी लाने जैसे कितनी ही तरह की ऊंट की उपयोगिता नजरअंदाज नहीं की जा सकती है।

दिया जा सकता है।

सरकार व स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से लगभग 260 गोवंश के पशुओं के शिविरों का आयोजन किया गया है जहाँ लगभग एक लाख पशुओं को निशुल्क चारा पानी मिलता है। इस समय सरकार प्रति गाय 12 रुपए की सहायता देती है। उसे यह सहायता रूपयों में न निर्धारित कर चारे की मात्रा में निर्धारित करनी चाहिए ताकि कीमते

कम से कम नौ दिन के लिए एक परिवार को रोजगार अवश्य मिल जाए। असहाय व्यक्तियों, परिवारों के लिए 50 किलोग्राम गेहूं की अलग व्यवस्था है। हालांकि कुछ जरूरतमंद लोग राहत कार्य या असहाय सहायता से अभी तक छूट रहे हैं, पर कुल मिलाकर प्रशासन के राहत प्रयास ने अनेक गांवों में अमीद जगाई रखी है व कई लोगों के संभावित

में कम से कम नौ दिन के लिए एक परिवार को रोजगार अवश्य मिल जाए। असहाय व्यक्तियों, परिवारों के लिए 50 किलोग्राम गेहूं की अलग व्यवस्था है। हालांकि कुछ जरूरतमंद लोग राहत कार्य या असहाय सहायता से अभी तक छूट रहे हैं, पर कुल मिलाकर प्रशासन के राहत प्रयास ने अनेक गांवों में अमीद जगाई रखी है व कई लोगों के संभावित PASHUPATI ROKEA है। दसरी ओर यदि

बताते हैं कि जब से खेती में ट्रैक्टर से जुताई हुई है, तब से स्वत - उपलब्ध होने वाले खाद्य, औषधि व चारे की दृष्टि से उपयोगी अनेक पेड़-पौधे व झाड़ खेतों से लुप्त होने लगे हैं। अतः हो सकता है कि एक दिन ट्रैक्टर अपनाने वाले किसान भी फिर से ऊंट की याद करें।

अकाल राहत कार्य को प्रशासन ने काफी व्यापक रूपर पर चलाया हुआ है जिससे उम्मीद यह रहती है कि एक माह

केंद्रीय सरकार ने राहत कार्य में खाद्यान्न की आपूर्ति कम कर दी तो इससे रोजगार में कमी आएगी व भूख की समस्या बढ़ेगी।

सीमा क्षेत्र होने के नाते यहाँ के अनेक गांवों के लिए सीमा क्षेत्रों के विशेष कार्यक्रम का बजट भी उपलब्ध है। पर महिला मंडल से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता आदिल भाई के अनुसार यह बजट शहरी भवन व क्रिकेट स्टेडियम बनाने जैसे कार्यों पर खर्च हो जाता है व गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। सामाजिक श्योर व सामाजिक अनुसंधान केंद्र जैसी संस्थाओं के दस्तकारी के कार्यों से अकाल के दिनों में कई ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलता है।

श्योर ने स्थानीय अच्छी नस्ल की थारयरकर गांवों के संरक्षण का कार्य भी किया है। बाड़मेर के नेहरू युवक केंद्र ने अनेक गांवों में पवित्र वनों ओरण की रक्षा करने व उन्हें नये जीवन देने के कार्य को प्रोत्साहित किया है। लीक अधिकार नेटवर्क ऐसे अनेक सारथक कार्यों में समन्वय बना कर अकाल से जूझने की एक व्यापक रणनीति निकालने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के परस्पर सहयोग से ही ऐसा एक समन्वित प्रमाण आगे बढ़ सकता है जिसमें तत्कालीन जरूरी राहत देने के साथ-साथ आत्मनिर्भर व हरे-भरे भविष्य की संभावनाएं भी नजर आती हों। ■